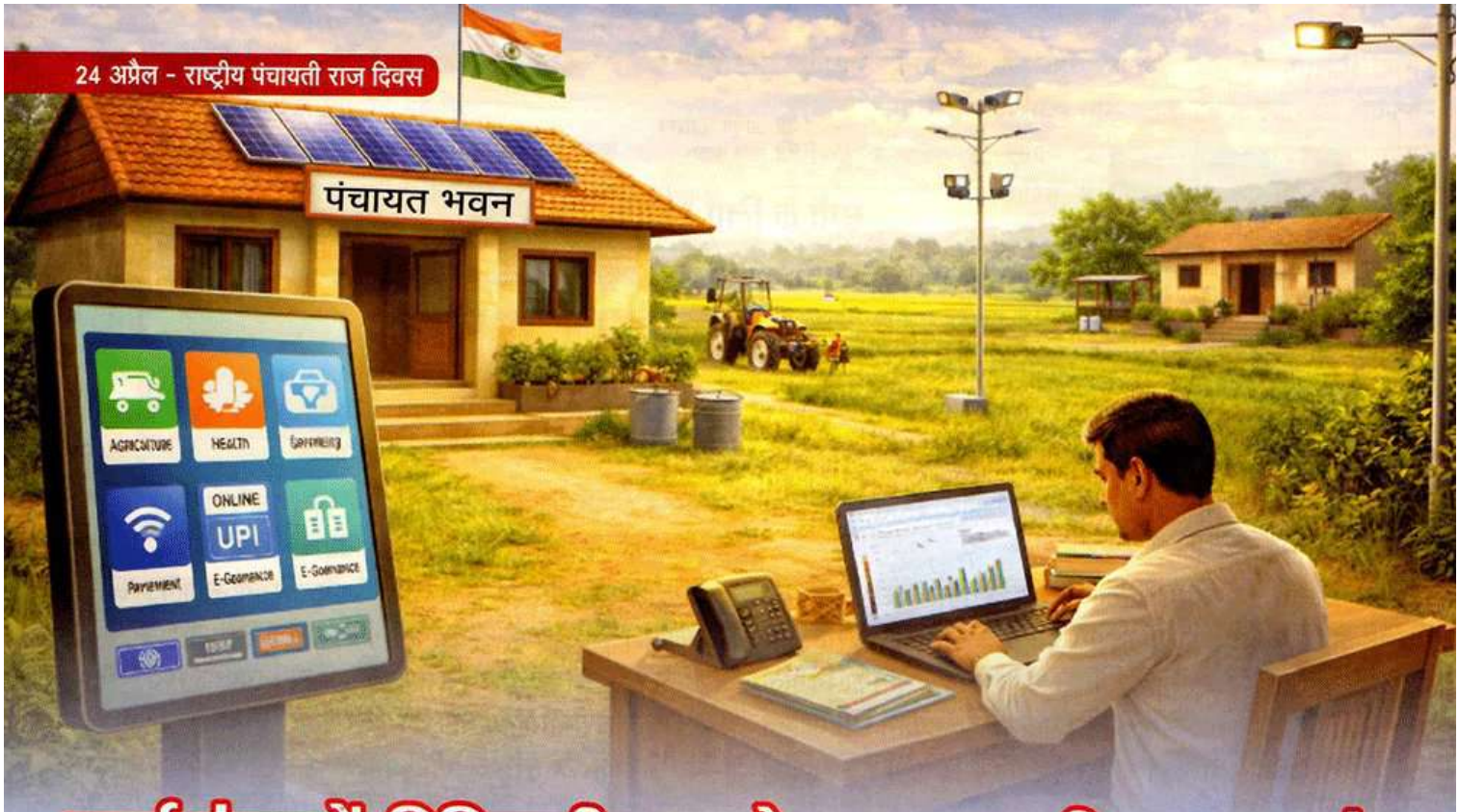

स्मार्ट पंचायतें: डिजिटलीकरण से बदलता ग्रामीण शासन तंत्र

डॉ. मोहसिन उद्दीन
डॉ. वसंथा गौरी

भारत के गाँव धीरे-धीरे डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं। ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन, ड्रोन-आधारित संपत्ति मानचित्रण और ग्राम सभा की कार्यवाही के डिजिटल अभिलेख जैसे कदम ग्रामीण शासन की कार्यप्रणाली को बदलने लगे हैं। इस परिवर्तन के केंद्र में पंचायती राज संस्थाएँ हैं, जो सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच सबसे नज़दीकी कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। देश में लगभग 2.68 लाख ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास की योजना बनाने, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ई-ग्रामस्वराज, स्वामित्व और भारतनेट जैसी डिजिटल पहलें पंचायतों को अधिक पारदर्शी, दक्ष और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायक बन रही हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तेज़ विकास ने पूरी दुनिया में सरकारों के काम करने के तरीके को बदल दिया है। भारत में डिजिटल तकनीक का उपयोग अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की आधारशिला मानी जाने वाली पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) धीरे-धीरे डिजिटल साधनों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अपना रही हैं। इन बदलावों के कारण ऐसी पंचायतों का विकास हो रहा है जिन्हें अक्सर 'स्मार्ट पंचायत' कहा जाता है।

स्मार्ट पंचायतें डिजिटल तकनीक का उपयोग करके स्थानीय शासन में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ाती हैं। भारत में लगभग 2.68 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए सबसे नज़दीकी प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करती हैं। इन संस्थाओं की ज़िम्मेदारी कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की होती

लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR), हैदराबाद के अंतर्गत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज में कंसल्टेंट हैं। ई-मेलः uddin.mohsin@gmail.com
लेखक उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में आईसीएसएसआर (ICSSR) में पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो हैं।

है, जैसे स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्थानीय बुनियादी ढाँचा, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और गाँव के विकास की योजना बनाना।

कई दशकों तक इन सेवाओं का प्रबंधन हाथ से लिखे रजिस्टरों और कागज़ आधारित प्रणालियों के माध्यम से किया जाता था। यद्यपि इन पारम्परिक तरीकों से पंचायतों का काम चलता रहा, लेकिन इनके कारण कई समस्याएँ भी पैदा हुईं जैसे काम में देरी, पारदर्शिता की कमी तथा सार्वजनिक धन और परियोजनाओं की निगरानी में कठिनाई। अब डिजिटल परिवर्तन इन समस्याओं को कम करने लगा है और धीरे-धीरे पंचायतों के कामकाज़ के तरीके को बदल रहा है।

ग्रामीण भारत में स्मार्ट पंचायतें

भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि समावेशी ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय शासन को मज़बूत करना आवश्यक है। जैसे-जैसे देश India @2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, पंचायतों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अधिक उत्तरदायी, कुशल और नागरिक-केंद्रित संस्थाएँ बनें। इस परिवर्तन में डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से पंचायतें योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कर पा रही हैं।

ग्रामीण शासन पर हाल की चर्चाओं में यह बताया गया है कि तकनीक संचार को बेहतर बनाकर, जानकारी तक पहुँच बढ़ाकर और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाकर गाँवों को बदलने की क्षमता रखती है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास पंचायत राज संस्थाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म पंचायतों को डिजिटल अभिलेख रखने, विकास परियोजनाओं की प्रगति का पता लगाने, वित्त का प्रबंधन करने और नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।

इन पहलों में eGramSwaraj पोर्टल पंचायतों में डिजिटल शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह पोर्टल पंचायतों को अपनी विकास योजनाएँ तैयार करने और अपलोड करने, वित्तीय खातों का रखरखाव करने, चल रही परियोजनाओं की निगरानी करने तथा गाँव के विकास से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

हाल की पहलें

eGramSwaraj प्लेटफ़ॉर्म को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से भी जोड़ा गया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को रियल-टाइम भुगतान संभव हुआ है। डिजिटल समावेशन से यह सुनिश्चित होता है कि विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि तेज़ी और पारदर्शिता के साथ स्थानांतरित हो। पहले मैनुअल प्रक्रियाओं और प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण भुगतान में अक्सर देरी होती थी। अब डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से भुगतान अधिक कुशलता से किए जा सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम करने और स्थानीय-स्तर पर वित्तीय जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलती है।

पंचायतों के कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण पहल 'मेरी पंचायत' मोबाइल एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन नागरिकों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से सीधे अपनी पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से ग्रामीण लोग पंचायत का बजट, विकास योजनाएँ, आधारभूत संरचना परियोजनाएँ तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। इस प्रकार की पारदर्शिता नागरिकों को सशक्त बनाती है, क्योंकि उन्हें ऐसी जानकारी तक पहुँच मिलती है जो पहले प्राप्त करना कठिन था। इससे स्थानीय सरकारों और ग्रामीण समुदायों के बीच विश्वास भी मज़बूत होता है।

डिजिटल तकनीक ने ग्राम सभा बैठकों के संचालन में भी सुधार किया है, जो ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन बैठकों में ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, योजनाओं को स्वीकृति देते हैं और पंचायतों के कार्यों की निगरानी करते हैं। पहले इन बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड मैनुअल रूप से रखा जाता था, जिससे कभी-कभी त्रुटियाँ या अधूरे अभिलेख रह जाते थे।

इस समस्या के समाधान के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने (*SabhaSaar*) नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण शुरू किया है, जो ग्राम सभा की कार्यवाही को स्वतः रिकॉर्ड कर उसका सार तैयार करता है। यह प्रणाली भाषण को लिखित पाठ में बदलकर बैठक का व्यवस्थित सार तैयार करती है। फरवरी 2026 तक 1,15,115 ग्राम पंचायतों ने इस उपकरण का उपयोग करके बैठकों के रिकॉर्ड तैयार किए थे। ऐसे डिजिटल उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राम सभा में हुई चर्चाएँ और निर्णय सही ढंग से दर्ज हों और भविष्य के लिए आसानी से उपलब्ध रहें।

Sabhasaar प्लेटफॉर्म को अपनाने की स्थिति राज्यों के बीच काफ़ी भिन्न है। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु (99.75%), ओडिशा (99.37%) और त्रिपुरा (90.95%) में इसका उपयोग बहुत अधिक है, जो ग्राम सभा की कार्यवाही में डिजिटल उपकरणों के प्रभावी समावेशन को दर्शाता है। झारखंड (79.82%), बिहार (79.28%) और छत्तीसगढ़ (75.84%) जैसे राज्यों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल (1.86%), असम (1.01%) और मणिपुर (0.88%) में इसका उपयोग अभी अपेक्षाकृत कम है। फरवरी 2026 तक देश की लगभग 2.68 लाख ग्राम पंचायतों में से 1.15 लाख पंचायतों में *Sabhasaar* के माध्यम

से ग्राम सभा की कार्यवाही दर्ज की जा चुकी थी, जो लगभग 43 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वीकृति को दर्शाता है।

ग्रामीण शासन को बदलने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल पहल 'स्वामित्व' (SVAMITVA) योजना है, जिसमें गाँवों की संपत्तियों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कई वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व के अभिलेख अक्सर अस्पष्ट या विवादित रहे, जिससे ग्रामीणों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से गाँवों में आवासीय संपत्तियों का सटीक मानचित्रण किया जाता है। इस मानचित्रण के आधार पर ग्रामीणों को आधिकारिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जो उनके स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

इस पहल के कई लाभ हैं। पहला, यह संपत्ति स्वामित्व के स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध कराकर भूमि संबंधी विवादों को कम करने में मदद करती है। दूसरा, यह ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक (कोलेटरल) के रूप में उपयोग करके बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तीसरा, इससे ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर संग्रह में सुधार करने और गाँव के विकास की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह योजना न केवल शासन को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी योगदान देती है।

डिजिटल योजना उपकरण भी पंचायतों को अधिक प्रभावी विकास परियोजनाएँ तैयार करने में सहायता कर रहे हैं। ऐसा ही एक उपकरण 'ग्राम मानचित्र' है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पर आधारित एक अनुप्रयोग है और पंचायतों को डिजिटल मानचित्रों की सहायता से विकास योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस मंच के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरण सड़कों, विद्यालयों, जल आपूर्ति प्रणालियों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सकते हैं। सटीक भौगोलिक आँकड़ों का उपयोग करके पंचायतें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि विकास परियोजनाओं की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जाए और उन्हें अधिक सटीकता के साथ क्रियान्वित किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन को सशक्त बनाने में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्थिर इंटरनेट सुविधा के बिना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकते। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देशभर की ग्राम पंचायतों को उच्च-गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'भारतनेट परियोजना' शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कि गाँवों को स्थिर इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध हों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना है।

भारतनेट के माध्यम से *फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क, वाई-फाई हॉटस्पॉट* और *फाइबर-टू-द-होम कनेक्शन* के द्वारा *ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी* उपलब्ध कराई जा रही है। इन नेटवर्कों के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स और डिजिटल सरकारी सेवाओं जैसी अनेक सुविधाओं तक पहुँच मिलती है। पंचायतों के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें योजना-निर्माण, निगरानी और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

पीएम-वाणी (Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface) पहल ने गाँवों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके ग्रामीण कनेक्टिविटी को और मज़बूत किया है। इन हॉटस्पॉट के माध्यम से ग्रामीण लोग किफ़ायती दरों पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और डिजिटल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। स्थिर इंटरनेट सुविधा विशेष रूप से किसानों, विद्यार्थियों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी दैनिक गतिविधियों में डिजिटल जानकारी और सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।

डिजिटल परिवर्तन पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता को भी सुदृढ़ बना रहा है। उदाहरण के लिए, *'ऑडिटऑनलाइन (AuditOnline) पोर्टल'* के माध्यम से सरकारी प्राधिकरण पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट कर सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म यह निगरानी करने में सहायता करता है कि धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और वित्तीय अभिलेखों का सही ढंग से संधारण हो रहा है। वित्तीय जानकारी को अधिक सुलभ और सत्यापन योग्य बनाकर डिजिटल ऑडिट प्रणालियाँ धन के दुरुपयोग को कम करने और जवाबदेही को मज़बूत करने में मदद करती हैं।

एक अन्य डिजिटल मंच 'पंचायत निर्णय' (Panchayat NIRNAY) ग्राम सभा बैठकों के प्रबंधन और निगरानी में सहायता करता है। यह पोर्टल पंचायतों को बैठकें निर्धारित करने, ग्रामीणों को बैठक के एजेंडा की जानकारी देने तथा चर्चाओं के दौरान लिए गए निर्णयों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि

ग्राम सभा की बैठकें अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आयोजित हों।

डिजिटल शासन ने पंचायतों और नागरिकों के बीच संचार को भी बेहतर बनाया है। मोबाइल अनुप्रयोगों और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से अब ग्रामीण पहले की तुलना में सरकारी जानकारी तक अधिक आसानी से पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कृषि योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान और बाज़ार मूल्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं।

स्मार्ट पंचायतें – लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना

डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से ग्रामीण शासन में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है। जब विकास योजनाओं, बजट और परियोजनाओं से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है, तो ग्रामीणों को अपनी पंचायतों के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यह जागरूकता उन्हें ग्राम सभा बैठकों और सामुदायिक निर्णय प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। परिणामस्वरूप, डिजिटल उपकरण ज़मीनी-स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत बनाने में सहायक हो रहे हैं। फिर भी, ग्रामीण शासन में डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

संभावित चुनौतियाँ

दूरदराज़ के कुछ गाँवों में कमज़ोर इंटरनेट कनेक्टिविटी एक प्रमुख बाधा है। यद्यपि इंटरनेट अवसंरचना में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में धीमा या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिलता है, जिससे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी उपयोग सीमित हो जाता है। कम डिजिटल साक्षरता भी ग्रामीण आबादी के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई ग्रामीण विशेष रूप से बुज़ुर्ग लोग, स्मार्टफोन या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से परिचित नहीं होते। इसके कारण डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिए उन्हें अक्सर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसे मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए स्मार्ट पंचायतों की सफलता के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता बढ़ाना आवश्यक है।

भाषायी बाधाएँ भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को प्रभावित करती हैं। कई ऑनलाइन सेवाएँ केवल अंग्रेज़ी या सीमित भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्रामीण नागरिक आसानी से समझ नहीं पाते। क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का विस्तार इस समस्या को दूर करने और तकनीक को ग्रामीणों के लिए अधिक सुलभ बनाने में सहायक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों की वहनीयता भी निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। यद्यपि समय के साथ तकनीक की लागत में कमी आई है, फिर भी कई ग्रामीण परिवारों के लिए इन उपकरणों को खरीदना और उनका रखरखाव करना कठिन होता है। समावेशी डिजिटल शासन सुनिश्चित करने के लिए इन आर्थिक बाधाओं का समाधान आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएँ भी डिजिटल तकनीक तक पहुँच को प्रभावित करती हैं। कुछ समुदायों में महिलाओं को स्मार्टफोन और डिजिटल शिक्षा तक सीमित पहुँच मिलती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि डिजिटल शासन के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें।

निष्कर्ष

स्मार्ट पंचायतों की अवधारणा भारत में ग्रामीण शासन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल अनुप्रयोगों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग से पंचायतें अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बन रही हैं। *eGramSwaraj, SVAMITVA, BharatNet, Meri Panchayat* और *Gram Manchitra* जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि तकनीक किस प्रकार स्थानीय शासन को मज़बूत कर सकती है और ज़मीनी-स्तर पर सेवा वितरण को बेहतर बना सकती है।

साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल परिवर्तन का लाभ सभी ग्रामीण समुदायों तक पहुँचे, डिजिटल साक्षरता, कनेक्टिविटी की कमी और उपकरणों की वहनीयता जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है, तो स्मार्ट पंचायतें भारत में अधिक सहभागी, जवाबदेह और डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण शासन प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ❑